सुलगते कश्मीर से और न खेलो

-वाई.के. रज्जन

क्या भारत सरकार ने कश्मीर में युद्ध घोषित कर दिया है...ताजा हालात यही बता रहे हैं। लेकिन उससे भी चिंताजनक बात ये है कि कश्मीर के लोगों ने इस युद्ध को स्वीकार कर लिया है और वे अब उसी रणनीति से जवाब दे रहे हैं। जिस बुरहान वानी को एनकाउंटर में मारने का दावा करने के बाद केंद्र सरकार और उसकी सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी पीठ थपथपाई, तब उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे कश्मीर को ऐसी आग में झोंकने जा रहा हैं, जिसका बुझना मुश्किल है। वह आग थम तो सकती है लेकिन धीरे-धीरे सुलगती रहेगी। कश्मीर में अब तक 35 लोग मारे जा चुके हैं और पूरे राज्य में लगता ही नहीं कि कोई सरकार काम कर रही है। सेना और पुलिस आपको मोर्चा लगाए दिखेंगे या फिर दीवारों पर नारे लिखे मिलेंगे...फ्री कश्मीर, इंडिया गो बैक, लॉन्ग लिव बुरहान वानी...ज्यादातर नारे अंग्रेजी में हैं। राज्य में बीजेपी के पसंद वाली सरकार है। यानी राज्य सरकार को केंद्र का पूरा समर्थन और साथ मिला हुआ है, इसके बावजूद राज्य के हालात इस तरह बिगड़ जाएं, तो सवाल उठने स्वाभाविक हैं। दिल्ली में कुछ लोगों ने चश्मा लगा रखा है और वे कश्मीर को उसी नजरिए से देखते और समझते हैं। इन चश्मे वालों को कश्मीर समस्या का एक ही हल दिखता है कि राज्य को सेना के हवाले कर दिया जाए। 2008 में जब इसी तरह भारी तनाव बन गया था, तब भी यही चर्चा चलाई गई। फिर 2010 में भी कुछ ऐसी कोशिश की गई। 2013 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जाते-जाते अफजल गुरु को फांसी देकर स्थिति को बदतर कर दिया। ये सारे निर्णय वे लोग ले रहे हैं जिन्होंने अलग तरह का कश्मीरी चश्मा लगा रखा है। कश्मीर की स्थिति पंजाब से थोड़ा अलग है। पंजाब में आतंकवाद फैला तो केंद्र सरकार उसे सख्ती से कुचलने में कामयाब रही और आखिरकार वहां से आतंकवाद का खात्मा हो गया। लेकिन कश्मीर में एक पीढ़ी को आप दबा ले जाते हैं तो दूसरी पीढ़ी हाथों में पत्थर लेकर तैयार मिलती है। 2010 की हिंसा में तो 100 से ज्यादा लोग मरे थे, मरने वाले ज्यादातर 10-20 साल के लड़के थे। लेकिन 2016 में उसी उम्र के नए लड़के हाथों में पत्थर लेकर दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ लोगों को आपकी सेना या पुलिस फायरिंग में मारकर यह मान लेती है कि उसने विरोधियों को कुचल दिया है लेकिन यही भूल है जो कश्मीर समस्या को खत्म नहीं होने दे रही है।

कश्मीरी युवक अचानक आक्रामक नहीं हुए हैं। उनकी कई पीढ़ी आज़ादी मांगते गुज़र गई।मौजूदा पीढ़ी इंटरनेट वाली है। उसने इंटरनेट पर खोज निकाला कि उनके दादा-नाना जिस आजादी की लड़ाई को लड़ते-लड़ते मर गए, वह सही थी और

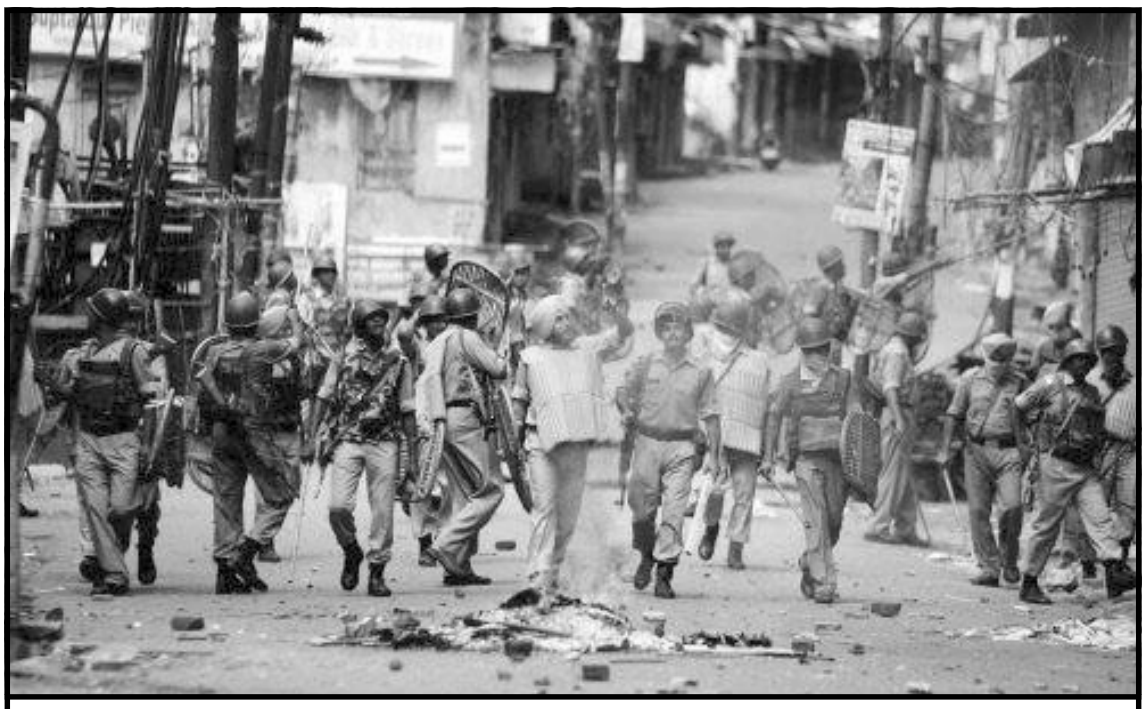

राजनीतिक मसले बंदूक से नहीं सुलझा करते

अब उनका फर्ज बनता है कि वे उस मुहिम को आगे बढ़ाएं। जिस राज्य में रोटी-रोजगार के बहुत साधन न हों और पर्यटन उद्योग पूरी तरह से तबाह हो चुका हो, वहां के युवकों के पास आजादी मांगने के अलावा और कोई काम ही नहीं है।

जिस बुरहान वानी की वजह से कश्मीर आज जल रहा है, 2010 की कश्मीर हिंसा में उसकी उम्र 16 साल थी। हाथों में एके-47 लिए उसके फोटो और विडियो जब फेसबुक और ट्विटर पर शेयर होने लगे तो कश्मीरी युवकों को लगा कि उन्हें उनका लीडर मिल गया है। वे उसके व्यक्तित्व से प्रभावित थे। कश्मीरी चश्मा लगाए लोगों ने रणनीति बनाई कि अगर बुरहान वानी को खत्म नहीं किया गया तो सममुच यह लड़का कश्मीर में तूफान मचा देगा। उसका एनकाउंटर हो गया। लेकिन उसके नमाज-ए- जनाजा में जो भीड़ उमड़ी, उससे भारत सरकार को सिरदर्द हो गया। त्राल में जहां उसे दफन किया गया, वहां तो हिंसा नहीं हुई लेकिन पूरे कश्मीर में बुरहान वानी को लेकर हिंसा हुई। हाथों में पत्थर लिए हुए बच्चे गलियों में सुरक्षा बलों पर बरसाते नजर आए। ये खतरनाक सीन है। भारत सरकार को समझना होगा कि ऐसा किन हालात में होता है। हैरानी है कि जो सरकार नगा विद्रोहियों को दिल्ली बुलाकर शांति वार्ता शुरू कर सकती है, उसे कश्मीरी गरम दल के नेताओं से बातचीत में इतना परहेज क्यों है। यह लगभग साफ है कि कश्मीरी अवाम न तो पहले नैशनल कॉन्फ्रेंस को और न अब पीडीपी को अपनी प्रतिनिधि पार्टी मानता है। ऐसे में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस समेत सभी धड़ों से केंद्र सरकार को बातचीत में शर्म क्यों महसूस हो रही है। आईबी, रॉ समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों में ऐसे अधिकारी हैं जो मानते हैं कि कश्मीरियों से बातचीत से ही इस मसले का हल संभव है, अब तक जितना दबाया जाना था, उन्हें दबा लिया गया लेकिन वे झुकने को तैयार नहीं। आखिर अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ऐसी पहल क्यों की गई थी...जाहिर है कि बीजेपी का उस समय का नेतृत्व आज के मुकाबले ज्यादा परिपक्व था। रामजेठमलानी समेत कई लोगों की एक टीम को वाजपेयी ने दौरे कश्मीर के दौरे पर भेजा था। खास बात ये थी कि इस टीम में कांग्रेसी भी शामिल थे। कश्मीर में वो दौर सबसे शांति का दौर था। इसके बाद जब दोबारा से डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार आई और अब मोदी सरकार है तो स्थितियों को भयावह बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई।

पाकिस्तान फैक्टर

कश्मीर में जब भी हिंसा शुरू होती है तो भारत सरकार सारा मसले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बता डालती है। पाकिस्तान को यह स्थिति पसंद है। क्योंकि उसके यहां की जनता भारतीय कश्मीरियों से हमदर्दी रखती है। इसके बाद एक से बढ़कर एक बयानबाजी दोनों तरफ से शुरू हो जाती है और असली मुद्दा दब जाता है। केंद्र सरकार इस बात को समझे कि कश्मीर समस्या का पाकिस्तान से इतना मतलब नहीं है जितना मतलब वहां की जनता से है। आपको समझना होगा कि कश्मीर की जनता ने भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। अगर कोई विद्रोह पर उतारू हो जाए तो उसे काबू करना मुश्किल हो जाता है। कश्मीरी लोग भारत के साथ नहीं रहना चाहते हैं। वे इस बात को कहने में जरा भी नहीं झिझकते। इसलिए तोप का मुंह पाकिस्तान की तरफ मोड़ने की बजाय कश्मीरियों से बातचीत की जाए। हालांकि पाकिस्तान से कश्मीर को लेकर खतरा हमेशा बना रहता है लेकिन हमें सच्चाई से भी मुंह नहीं चुराना चाहिए। ये ठीक है कि पाकिस्तान मौके का फायदा उठा सकता है लेकिन आपको अपना घर ठीक करने से किसने रोका है। कश्मीर के जिन हिस्सों में शांति रहती है या उतनी ज्यादा समस्या नहीं है, आखिर वहां सेना को विशेष अधिकार क्यों मिलना चाहिए। सैन्य अधिकारी इस बात पर क्यों नहीं नजर रखते कि सेना का कोई भी जवान आम कश्मीरी महिला या बच्चों के साथ कोई उल्टी-सीधी हरकत न करे।

मीडिया की भूमिका

कश्मीर के मामले में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की भूमिका बेहद शर्मनाक है। वे सारे मामले को देशभक्ति के नजरिए से देखते हैं और माहौल को बिगाड़ने का ही काम कर रहे हैं। आप भारत का कोई भी टीवी चैनल खोलिए, हर कोई दूसरे से बड़ा स्वयंभू देशभक्त और देश की चिंता करने वाला साबित होना चाहता है। प्रिंट मीडिया में हिंदी के समाचारपत्रों की भूमिका बहुत ही शोचनीय है।

ज्यादातर अखबारों में आरएसएस के लोग भरे हुए हैं और वे उसी मानसिकता से खबरें व लेख भी छापते हैं। इन अखबारों के दफ्तरों का हाल उससे भी बुरा है। दफ्तर में ही एक दूसरे के मुकाबले राष्ट्रभक्त होने की दुहाई दी जाती है। पत्रकारिता में जिस गंभीरता की जरूरत होती है, वो कम से कम हिंदी अखबारों से बहुत दूर हो चुकी है।

ईलाज के नाम पर ठगने वाले ईएसआई निगम के विरुद्ध मज़दूरों का संघर्ष

फ़रीदाबाद (म.मो.) यों तो अपने नागरिकों को चिकित्सा सुविधा देना सरकार का दायित्व है। इसके बावजूद औद्योगिक मज़दूरों को विशेष चिकित्सा सुविधा एवं सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1952 में ईएसआईसी (राज्य कर्मचारी बीमा निगम) एक्ट संसद द्वारा पास किया गया। इसमें वर्णित तमाम सुविधायें ब्रिटिश स्वास्थ्य सेवा की तर्ज पर रखी गयी थी जो अपने आप में एक बेहतरीन व्यवस्था थी।

इस एक्ट के मुताविक न तो केन्द्र सरकार और न ही राज्य सरकार इस योजना में एक भी पैसा खर्च करेगी। सारा पैसा मज़दूरों से ही अंशदान के रूप में वसुला जाना तय हुआ था जो कि आज तक जारी है। इसके अनुसार 15 हज़ार रुपये मासिक वेतन पाने वाले प्रत्येक मज़दूर से वेतन का साढे 6 प्रतिशत वसूला जाता है। इस पैसे के बदले ईएसआई निगम की जिम्मेदारी बनती है कि वह अंशदान करने वाले मज़दूर व उसके परिवार को समुचित चिकित्सा सुविधा प्रदान करे। इसके अलावा दुर्घटना अथवा मृत्यु होने पर मज़दूर को वित्तीय सहायता/पेंशन देवें।

ईएसआई निगम मज़दूर से पैसा काटना तो कभी भूलता नहीं लेकिन उसके बदले में चिकित्सा सुविधा देने का अपना दायित्व नहीं निभा रहा। आज अकेले हरियाणा में करीब 18 लाख मज़दूरों से ईएसआई निगम 1000-1200 करोड़ रुपया सालाना वसूली कर रहा है। लेकिन चिकित्सा के लिये आनेवाले इन मज़दूरों को निगम धक्के खिलाने व चक्कर कटाने के अलावा कुछ खास नहीं दे रहा।

ई एसआई निगम की अपनी नियमावली के अनुसार प्रत्येक 10000 मज़दूरों पर पांच डॉक्टर व पच्चीस अन्य स्टाफ़ की एक डिस्पेंसरी होनी चाहिये जिसमें तमाम दवाईया एवं सुविधायें होनी चाहिये। इस हिसाब से राज्य भर में 900 डॉक्टर व 4500 अन्य स्टाफ़ डिस्पेंसरियों में होना चाहिये। इसके विपरीत राज्य भर में केवल 180 डॉक्टर व करीब 500 अन्य स्टाफ़ मौजूद है। डॉक्टरों व स्टाफ़ की इस कमी का खामियाज़ा मज़दूरों को तो भुगतना पड़ता ही है डॉक्टर व स्टाफ़ भी काम के बोझ से दबकर परेशान रहते हैं।

डिस्पेंसरियों के अतिरिक्त 5 लाख कार्ड होल्डर मज़दूरों के लिये 500 बेड का एक अस्पताल होना चाहिये। जिसमें 200 डॉक्टर व 1200 अन्य स्टाफ़ होना चाहिये। यह बात कोई और नहीं स्वयं ईएसआई की नियमावली में लिखी है।

फ़रीदाबाद में 6 लाख से अधिक कार्ड होल्डर हैं जिनको न तो डिस्पेंसरियों की पर्याप्त सुविधा मिल पा रही है और न ही अस्पताल की। यहां पर हाल-फ़िलहाल दो अस्पताल है। एक अस्पताल सेक्टर 8 में है जिसकी दुर्दशा का वर्णन अनेकों बार 'मज़दूर मोर्चा' में किया गया है। न तो वहां पर्याप्त डॉक्टर व स्टाफ हैं न दवायें हैं न आवश्यक उपकरण। डिस्पेंसरियों से भटकते हुए मज़दूर जब इस अस्पताल में पहुंचते हैं तो उन्हें ईलाज करने के बजाय दूसरे अस्पतालों के लिये रेफ़र किया जाता है। यहां पर पेच यह है कि एन-एच 3 वाले केवल अपने मरीज़ों को कैशलेश सुविधा के साथ निजी अस्पतालों में भेजते हैं। जबकि सेक्टर 8 वाले अपने मरीज़ों को निजी अस्पतालों में तो भेजते हैं लेकिन उसका अग्रिम भुगतान स्वयं मज़दूर को करना पड़ता है। जिसकी वसूली के लिये मज़दूर महीनों-वर्षों चक्कर लगाता रहता है, तब भी पूरे पैसे नहीं मिल पाते।

ईएसआई एक्ट के मुताविक जब मज़दूर निगम को अग्रिम भुगतान कर चुका होता है तो उसे सारी चिकित्सा सुविधायें मुफ़्त व तुरन्त मिलनी चाहिये; लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। मज़दूरों द्वारा बार-बार ज्ञापन दिये जाने व बार-बार प्रदर्शन किये जाने के बावजूद किसी अधिकारी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इन हॉलात में मज़दूरों ने तमाम डिस्पेंसरियों व अस्पतालों पर प्रदर्शन करने का अभियान शुरू कर दिया है। इसी श्रृंखला में शीघ्र ही सेक्टर 16 स्थित ईएसआई के क्षेत्रीय निदेशक कार्यालाय पर प्रदर्शन व जरूरी हुआ तो घेराव करने की योजना बनाई है। यदि इससे भी निगम व सरकार नहीं चेती तो मज़दूर और अधिक संगठित होकर अपने संघर्ष को और तीखा करेंगे। ईएसआई द्वारा की जा रही इस लूट को मज़दूर अब और बर्दाश्त करने वाला नहीं है। मज़दूरों को सुविधाओं से वंचित रखकर ईएसआई निगम ने अपना खज़ाना भरते-भरते 40 हज़ार करोड़ का मुनाफ़ा एकत्रित कर लिया है। मज़दूरों को सुविधायें देने की अपेक्षा हेमा मालिनी द्वारा टेलिविजन चैनलों पर मज़दूरों को भ्रमित करने की चालबाज़ी अब और नहीं चलने दी जायेगी।

ईएसआई की गुंडागर्दी व लूट खसूट के विरुद्ध लामबंद होते मज़दूरों की गोष्ठी रविवार दिनांक 17 जुलाई 2016 को एसी नगर के सामुदायिक भवन (निकट डिलाइट होटल) में प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक होगी। सभी आमन्त्रित हैं।

-सम्पर्क 7053611692

9999946920